तोड़नी ही होगी यह अजगरी निद्रा

राजसत्ता

प्रभात कुमार रॉय

अंततः खूनी काले बुधवार को बर्बर आतंकवादी मुंबई पर बर्बर खूनी निशाना लगाने में एक बार फिर से कामयाब हो ही गए। सन 1993 में प्रथम बार मुंबई पर ब्लैक ब्लडी वैडनसडे (खूनी काले बुधवार) को ही जेहादी आतंकवादियों ने बर्बर आक्रमण अंजाम दिया था। तब से तकरीबन 14 बार मुंबई महानगर पर आतंकवादी आक्रमण अंजाम दिए गए। आतंकवाद के गहन प्रश्न पर हुकूमत ए हिंदुस्तान को नाकाम करार दिया जा सकता है। अमेरिका को जेहादी आतंकवादी महज एक मर्तबा ही 11 सितंबर 2001 को ही अपना बर्बर निशाना बना सके। 9/11 के आतंकवादी आक्रमण के पश्चात अमेरिका को जेहादी पुनः निशाना नहीं बना सके। अमेरिका ने अपनी संपूर्ण सैन्य शक्ति को जेहादी आतंकवाद के तमाम गढ़ों को तहस-नहस करने में झोंक दी। किंतु इसके विपरीत भारतीय राजसत्ता में राजनीतिक इच्छा कदापि नहीं रही। कुछ दिनों की सक्रियता के बाद अगला आक्रमण होने तक सभी अजगरी निद्रा में सो जाते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम ने दो साल पूर्व एंटी टैरेरिस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव किया, किंतु प्रस्ताव सरकारी फाइलों से आगे नहीं बढ़ सका। आतंकवाद पर नेशनल इंवैस्टिगेशन एजेन्सी (एनआईए) के गठन के बावजूद केंद्र और प्रांतीय सरकारों की खुफिया एजेन्सियों के मध्य बेहद जरुरी तालमेल का गहन आभाव कायम रहा।

जहां अमेरिका में एक लाख की आबादी पर औसतन 100 खुफिया एजेन्ट्स तैनात रहे और रशिया एवं चीन में एक लाख की आबादी पर औसतन 150 खुफिया एजेन्ट्स की तैनाती बनी रही। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के सर्वोच्च निशाने पर कायम रहे, भारत में एक लाख की आबादी पर औसतन मात्र 10 खुफिया एजेन्ट्स ही तैनात रहे। प्रत्येक आतंकवादी आक्रमण के पश्चात प्रायः इसे खुफिया तंत्र की नाकामी करार दिया जाता रहा। आतंकवाद से मुकाबला करने चली भारत की इंटरनेशनल खुफिया ऐजेन्सी रॉ के पास मात्र कुछ हजार एजेन्ट्स हैं जबकि आईएसआई केएक लाख से अधिक एजेन्ट्स हैं।

आज देश की संसद में विपक्ष में विराजमान राजनेता पूरे छः वर्षों तक, 1998 से 2004 तक बाकायदा केंद्रीय राजसत्ता पर काबिज बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय जेहादी आतंकवाद के जटिल प्रश्न पर लचर-मचर शासकीय नीति पर मनमोहनी यूपीए हुकूमत कायम रही, तकरीबन ऐसी शासकीय नीति अटल जी की एनडीए सरकार की भी रही। अमेरिका के कूटनीतिक दबाव में पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ बेहद नरम रवैया अख्त्यार किया और उनके मूल चरित्र को कदाचित संज्ञान में न रखते हुए, उन पर गैर जरुरी भरोसा किया गया। परिणामस्वरुप कूटनीतिक बातचीत के आगाज में पाक सेना ने जेहादियों को आगे कर करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा किया। ऐतिहासिक गलतियों से कदाचित कोई सबक न सिखकर मनमोहनी यूपीए हुकूमत पुनः वही भूल दोहराने पर आमादा है। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव के तहत कभी कश्मीर को बलपूर्वक हड़प करने की शासकीय नीति का परित्याग कर दिया। क्या पाकिस्तान ने कश्मीर जेहाद का संचालन करने आतंकवादी जेहादी गुटों को प्रश्रय प्रदान करना बंद कर दिया। क्या आईएसआई ने आतंकवादी प्रशिक्षण शिवरों को बंद कर दिया। यदि नहीं तो फिर आखिर किस ठोस धरातल पर वार्ता का कूटनीतिक आयोजन जारी है। भारत को संजीदगी के साथ यदि आतंकवाद से निपटना है तो कूटनीतिक दबावों को दरकिनार करते हुए अपने गहन राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध अपनी शासकीय नीति का फिर से निर्माण करना होगा। दलगत पूर्वाग्रहों और राजनीतिक मौकापरस्ती का परित्याग करके ही आतंकवाद के प्रश्न पर राष्ट्रीय सहमति का तत्काल सृजन होना चाहिए। भारतीय खुफिया नेटवर्क को विश्व स्तर की कसौटी का निर्मित करने के बेहद कड़े प्रयास किए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को किसी खास मजहब से संबद्ध कर-के देखने की प्रवृति का खात्मा होना चाहिए। इसके लिए साहिर लुधयानवी की उल्लेखनीय कारगर पंक्तियों का स्मरण करें। किसी बर्बर की कोई कौम न, कोई मजहब न, कोई जात। उसके लिए इन अल्फाज का जबान पर लाना हराम है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

Reproduced by www.hobbyhobby.com with author's permission